दैनिक यशोभूमि
नया तेवर, नया कलेवर
मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, पुणे और नासिक से एक साथ प्रकाशित

महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक रोड फ्रेट में बदलाव की जरूरत

यशोभूमि/ प्रतिनिधि

मुंबई। महाराष्ट्र के पास इलेक्ट्रिक रोड फ्रेट की ओर बदलाव में लीडरशिप पोजीशन लेने का मौका है। अपने मजबूत इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स बेस के साथ, राज्य कमर्शियली वायबल मॉडल बनाने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिससे इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक ट्रक अपना सके। अब फोकस एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने पर होना चाहिए जो

इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर अपना सके इलेक्ट्रिक ट्रक

कार्गो मालिकों, फ्लीट ऑपरेटरों, गाड़ी बनाने वालों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनर्जी प्रोवाइडर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को एक साथ लाए। महाप्रीट के मैनेजिंग डायरेक्टर बिपिन श्रीमाली ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में महाप्रीट (महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड) और इंटेंट द्वारा आयोजित 'महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक रोड



फ्रेट में बदलाव को तेज करना' विषय पर राउंड टेबल में कहा। श्रीमाली ने आगे कहा कि इलेक्ट्रिक-ट्रकिंग इकोसिस्टम अभी 'चिकन-एंड-एग' चैलेंज का सामना कर रहा है, जिसमें यूजर्स गाड़ियों को खरीदने से पहले सही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को इन्वेस्टमेंट को सही ठहराने के लिए काफी डिमांड चाहिए। उदाहरण के लिए, महाप्रीट पूरे भारत के मैंडेट के साथ और एनएचएआई के साथ पहली बार राइट-ऑफ-वे एक्सेस को इनेबल करने के साथ 64 बड़े ईवी चार्जिंग स्टेशन डेवलप कर रहा है। इंटेंट की फाउंडर और सीईओ महुआ आचार्य ने कहा कि भारत में लगभग 4 मिलियन रजिस्टर्ड ट्रक हैं, जबकि 1,000 से भी कम इलेक्ट्रिक हैं। यह हमारे सामने मौजूद मौके के बड़े पैमाने को दिखाता है। भारत के कुल एमिशन में ट्रांसपोर्ट का हिस्सा लगभग 10% है, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट का हिस्सा सबसे ज्यादा है। हालांकि पॉलिसी का माहौल और इंसेंटिव तेजी से अच्छे हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रकिंग को आखिरकार कम टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, पक्की फ्रेट डिमांड, सही फाइनेंसिंग और सही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए मजबूत कमर्शियल समझ बनानी होगी।

विकसित भारत के विजन की ओर बढ़ रहा है भारत

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के चेयरमैन और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट डॉ. विजय कलंत्री ने अपनी बात में कहा कि जैसे-जैसे भारत 'विकसित भारत 2047' के विजन की ओर बढ़ रहा है, हमारा लॉजिस्टिक्स सिस्टम ज्यादा कुशल, टिकाऊ और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनना चाहिए। चीन की तुलना में, जहां लगभग 400 हजार इलेक्ट्रिक ट्रक बिके, भारत में सिर्फ 1000 यूनिट बिके। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% क्रूड-ऑयल इम्पोर्ट करता है, इसलिए माल ढुलाई का इलेक्ट्रिफिकेशन एनर्जी सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और कॉम्पिटिटिवनेस से गहराई से जुड़ा हुआ है।